

## जोखिम और गवर्नेंस के परिप्रेक्ष्य में\* आनंद सिन्हा

श्री पी. आर. रमेश, अध्यक्ष, डिलॉयट, डॉ. विक्रम कुरियन, निवेश केंद्र के निदेशक, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, सुश्री ऊषा थोरात और वी.एस. दास, रिजर्व बैंक के मेरे पूर्व सहकर्मियों और अन्य प्रतिनिधि मंडल के सदस्य। यह मेरे लिए हर्ष बात है कि मैं आज इस शिखर सम्मेलन के अवसर पर आप से बातचीत कर रहा हूँ।

2. इस शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु जोखिम और गवर्नेंस से संबंधित है, ये वे दो शब्द हैं जिनको नीति निर्माताओं द्वारा वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात नयी रुचि और एक नए परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। मैं नियामक परिवर्तनों (बासेल III) पर चर्चा करने के पहले अवधारणात्मक दृष्टि से जोखिम और गवर्नेंस दोनों पर संक्षेप में बात करना चाहता हूँ और भारतीय परिप्रेक्ष्य की संक्षिप्त समीक्षा करने के पश्चात इसे समाप्त करूँगा।

3. गुणों में जोखिम लगभग भगवान् तुल्य है। यह सर्वव्यापी है। आपको ठहलने (आपके फिसलने और गिरने का जोखिम है) अथवा बातचीत करने (आपके द्वारा कुछ अनुचित बोलने अथवा उसकी गलत व्याख्या किए जाने का जोखिम है) जैसी साधारण बातों से लगाकर उड़ने वाले वायुयानों, उपग्रह भेजने या शाल्य क्रिया करने जैसी गंभीर बातों का हर जगह जोखिम है। जोखिम का प्रबंधन करना घातक साबित हो सकता है तथा हाल का वैश्विक संकट इस बात का जीता जागता साक्ष्य है।

4. जोखिम का एक लंबा इतिहास है, शायद मानवीय इतिहास की तरह और जोखिम प्रबंधन का भी इसी तरह का इतिहास है। प्रारंभिक युग में जोखिम और जोखिम प्रबंधन जैसा था, इस पर प्रकाश डालते हुए मुझे एक सुंदर उदाहरण याद है जो इस प्रकार है: ‘अफ्रीका में हर रोज चिंकारा जागता है। वह जानता है कि उसे शेर से ज्यादा तेज दौड़ना है अन्यथा उसे मार डाला जाएगा। हरेक सुबह शेर जागता है। वह जानता है कि उसे बहुत धीमे चलने वाले चिंकारा को पछाड़ना

है अथवा उसे भूखों मरना पड़ेगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शेर हैं या चिंकारा। जब सूरज बाहर निकल आता है, तो आपके लिए तेज दौड़ना ही बेहतर है। जोखिम को समझना और उसका प्रबंधन करने की सीख लेना किसी भी युग में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में अस्तित्व के लिए एक मंत्र रहा है। वास्तव में, मैं कहना चाहूँगा कि जोखिम का प्रबंधन करना मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण है जो इसे अन्यों से अलग करता है और उसके अस्तित्व और विकास में सहायता करता है।

5. जबकि जोखिम हर जगह है, मैं अपनी चर्चा में वित्तीय जगत पर बल देना चाहूँगा, जहाँ पर कई तरीके से जोखिम को संख्यावाची बनाने और उसका प्रबंधन करने के कई प्रयास किये गए हैं।

### II वित्तीय जगत में जोखिम और जोखिम प्रबंधन

6. अतीत में कई बार, वित्तीय जोखिमों ने कई आघात दिए हैं जिससे प्रणाली से बिलियन डालर की संपदा का सफाया हुआ और लोगों तथा अर्थव्यवस्थाओं को दिवालियेपन की ओर अग्रसर होना पड़ा। 1987 का स्टॉक बाजार क्रैश, 2000 का डॉटकाम बस्ट तथा हाल का और अभी बिल्कुल ताजा 2007 का संकट, ऐसे कुछ उल्लेखनीय उदाहरण हैं जब जोखिम नियंत्रण से बाहर हो गए और वे जोखिम के कुप्रबंधन के संभावित प्रभाव की याद दिलाने वाले हैं।

7. कई कारकों, समष्टिआर्थिक और विनियामक एवं पर्यवेक्षी दोनों, ने 2007 के संकट को इस विशाल आयाम तक बढ़ा दिया। जोखिम मॉडलिंग के व्यापक विकास और अत्याधुनिक होने के बावजूद अंतिम विश्लेषण यही है कि जोखिम मापांकन और प्रबंधन उपकरण तथा कार्यप्रणाली पूरी तरह से अपर्याप्त साबित हुई है।

8. ग्रेट मॉडरेशन की अवधि के दौरान जोखिम के बहुत कम मूल्यांकन का परिणाम लीवरेज की अधिकता के रूप में हुआ। अल्पकालिक थोक निधीयन पर अधिक निर्भरता के साथ-साथ इसका परिणाम यह हुआ कि अमरीकी के सब-प्राइम बंधक बाजार में उत्पन्न स्ट्रेस के कारण आस्ति मूल्यों के नीचे गिरने का चक्र शुरू हुआ जिससे अमरीका और समस्त विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का अधोमुखी पतन

\* 23 अगस्त 2012 को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद तथा डिलॉयट द्वारा आयोजित जोखिम और गवर्नेंस शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, श्री आनंद सिन्हा द्वारा दिया गया भाषण। सुश्री रजना सहजवाला, सुश्री अनुपम सोनल तथा जया कुमार आरासी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के लिए हम आभारी हैं।

हुआ। इस संकट का प्रभाव बहुत अधिक और लंबा हुआ तथा यह अनुमान लगाना कठिन है कि विश्व अर्थव्यवस्था के कब ‘सामान्य’ होने की संभावना है। साफ तौर पर यह कार्पोरेट गवर्नेंस की विफलता का मामला है क्योंकि जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां नहीं अपनाई गईं।

9. संकट ने संख्यात्मक वित्तीय मॉडल के स्वरूप और आपदा की भविष्यवाणी करने की उनकी अक्षमता में बहुत अधिक रुचि उत्पन्न की। इससे स्पष्ट है कि प्रयोग में लाए जा रहे जोखिम मॉडल बहुत अधिक अपर्याप्त थे। ज्यादातर हानियां ट्रेडिंग बुक में हुई जहाँ संकट के दौरान एकत्रित हानियां, भविष्यवाणी किए गए जोखिम मूल्य मॉडल की तुलना में कई गुना अधिक थीं। इसके अलावा, संकल्पनात्मक ढांचे में गंभीर कमियां थीं क्योंकि जोखिम प्रबंधन इस गलत धारणा के कारण अलग-अलग बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं पर लगभग पूरी तरह से केन्द्रित किया गया था कि वैयक्तिक तौर पर मजबूत वित्तीय संस्थाएं एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली का निर्माण करें। इस गलत धारणा को धोखों के समूहन के रूप में जाना जाता है और उसका दुष्परिणाम प्रणालीगत जोखिम के रूप में हुआ जिस पर अति आवश्यक गंभीर विचार नहीं किया गया। इस प्रकार प्रणालीगत जोखिम अर्थात् वित्तीय प्रणाली में चक्रीय अनुकूलता और अंतर्संबद्धता के निराकरण के लिए कोई ढांचा नहीं था।

10. इसलिए संख्यात्मक मॉडल की सीमाओं का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। बाजार जोखिम के लिए जोखिम मूल्य मॉडल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सरल है और इसकी गणित को समझा जा सकता है। जोखिम मूल्य मॉडल को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बासेल समिति का नियामक अनुमोदन प्राप्त है और इसलिए देश के नियामकों से भी मान्यता प्राप्त है। यह मॉडल दो मान्यताओं पर कार्य करता है:

- सामान्यता - अर्थात् आस्ति मूल्य सामान्य वितरण का अनुपालन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि यह वास्तविकता का अनुमान है क्योंकि वास्तव में मॉडल, परिभाषा के अनुसार वास्तविकता का संक्षेपीकरण हैं। लेकिन, कुछ अवधियों में विशेष रूप से उच्च स्ट्रेस की स्थिति में सामान्यता अनुमान वास्तविकता से अवहनीय रूप से अमूर्त है।
- जोखिम मूल्य मॉडल नैमित्तिक नहीं है लेकिन स्वरूप में सांख्यिकीय है और इसलिए वे भावी आस्ति मूल्यों की भविष्यवाणी करने के लिए अतीत के आंकड़ों का प्रयोग करते हैं।

11. त्रहण जोखिम के लिए भी, आंतरिक दर आधारित बासेल ढांचे के अंतर्गत पूँजी आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए स्वरूप में वासीसेक मॉडल का प्रयोग किया जाता है। इस मॉडल में भी, यह माना जाता है कि अंतर्निहित जोखिम कारकों और अब पोर्टफोलियो हानियों को सामान्यतयः संवितरित किया जाता है।

12. सामान्य वितरण के अंतर्गत, माध्य परिणाम (3 मानक विचलनों अथवा सिगमा से अधिक) से और अधिक घटनाओं के होने की संभावना तेजी से गिरी। उदाहरण के लिए, किसी दिवस पर 5 सिगमा हानि की संभावना का तात्पर्य होगा कि इस प्रकार की घटना लगभग 14,000 सालों में (वर्ष में 250 ट्रेडिंग दिवस मानते हुए) एक बार होगी, यह उस अवधि से अधिक होगी जो सभ्यता के विकसित होने के पहले समाप्त हो गई।<sup>1</sup> लेकिन, संकट के दौरान वाल स्ट्रीट जर्नल (2007) में कहा गया कि वे घटनाएं, जिनके बारे में मॉडल ने भविष्यवाणी की कि वे 10,000 वर्षों में केवल एक बार होंगी, पर वे 3 दिनों के लिए प्रतिदिन घटित हुईं। फाइनेंशियल टाइम्स 2007 में डेविड विनियर, गोल्डमैन सैच के मुख्य वित्तीय अधिकारी को उद्धत करते हुए कहा गया ‘हम उन चीजों को देख रहे हैं जो 25 मानक विचलन के उतार-चढ़ाव में हैं, और वे क्रमशः कई दिनों तक बनी रहीं। अन्य संख्यावाली स्पेस के कुछ मामले रहे हैं। लेकिन, ऐसा कोई नहीं जिसको हमने पिछले हफ्ते देखा।’<sup>2</sup> ऐसे बड़े-बड़े सिगमा उतार-चढ़ाव पहले भी हुए हैं। 1992 में यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के दौरान ब्याज दरों में 50 सिगमा उतार-चढ़ाव देखे गए, जबकि 1987 का ब्लेक मंडे एक 20 सिगमा की घटना थी। 1988 के ग्रीष्म उथल-पुथल, जिसने उसी समय दीघविधि पूँजी प्रबंधन को नीचे गिराया, के दौरान 15 प्लस सिगमा विचलन हुए जो परम्परा बन गए<sup>3</sup>। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संभावना वितरण में सामान्यता की मान्यता वास्तविकता के अनुरूप नहीं है विशेष रूप से अधिक तनाव की स्थिति में।

13. सामान्य वितरण के पीछे अंतर्निहित मान्यता यह है कि यह बड़ी संख्या में सहभागियों वाले एक सामूहिक बाजार का प्रतिनिधित्व करता है जो सहभागी तर्कसंगत रूप से और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं और उनका व्यवहार सभी समय क्षेत्रों में स्थिर रहता है जिससे अतीत के आंकड़ों से भविष्यवाणी करने में आसानी होती है। समीप

<sup>1</sup> दौड़, केबिन और हुचिसन, मार्टिन, ‘एल्केमिस्ट्स ऑफ लॉस’, टाइम्स ग्रुप बुक्स।

<sup>2</sup> डेनियलसन, जॉन ‘ब्लेम दि मॉडल’, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 4 (2008)।

<sup>3</sup> द्वियाना, पेबलो (2009), ‘लेक्चरिंग बर्डस ऑफ फ्लाइंग’ जॉन विली एंड संस आईएनसी।

से समीक्षा करने पर यह मान्यता बहुत अधिक सटीक नहीं है क्योंकि आर्थिक एजेंट समाचारों और जानकारियों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तथा वे अतार्किक व्यवहार पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में यह समाचार या तो बहुत अधिक अच्छा होता है या बहुत अधिक निराशाजनक। वास्तव में, यह व्यवहार ‘निकट दूर दृष्टि’ से प्रेरित होता है और इसलिए जब निराशा घर कर लेती है तो वे समूह व्यवहार करने लगते हैं जिससे आस्तियों के मूल्य बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं जिसके परिणामस्वरूप वितरण में असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है : अर्थात हानियां जोखिम मूल्य मॉडल की भविष्यवाणी की तुलना में अधिक होती हैं। संकट की स्थिति में यह उन सह संबंधों में बड़ा झुकाव है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं और एक ऐसे मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं जो सीमित प्रयोग के लिए ऐसे परिवर्तनों की अनुमति नहीं देते हैं। संकट के दौरान जोखिम मॉडलिंग की विफलता का श्रेष्ठ उदाहरण सीडीओ है क्योंकि एक बार जब सब प्राइम गिर्वी खंड में तनाव की स्थिति आ गई तो ये मॉडल सहसंबंधी चूकों को हिसाब में लेने में विफल रहे। यह इस मनोविज्ञान और तेजी की अवधि से लाए गए ऋण बोझ के कारण हुआ है कि सभी प्रोत्साहनों के बावजूद उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि में गति नहीं आई। हमारा यह भी अनुभव रहा है कि संकट की शुरुआत के बाद जबसे मौद्रिक और समष्टि विवेकपूर्ण मानदंडों को तेजी से आसान बनाया गया, ऋण का कोई अधिक उठाव नहीं हो सका।

14. चूंकि अतीत, भविष्य का एक अच्छा संकेतक रहा है, यह मान्यता बहुत अधिक दोषपूर्ण है। प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास, बाजार के वर्धित समन्वयन और नवीनतम खिलाड़ियों के प्रवेश के कारण वर्तमान और अतीत, भूत से बहुत अधिक भिन्न हो गया है और अतीत के आंकड़ों के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना बहुत ही सरल बात हो गई है। पेबलो ट्रियाना ने अपनी पुस्तक, ‘लेक्चरिंग वर्ड्स ऑन फ्लाइंग’ में संक्षेप में तर्क-दिया है कि एलटीसीएम ने अपने अल्पकालिक मॉडलों के साथ भविष्य का अनुमान लगाने का प्रयास किया, लेकिन इसने यह महसूस करने में भयानक गलती की कि एलटीसीएम से रहित अतीत, एलटीसीएम प्राधान्य वाले वर्तमान का एक भरोसेमंद दिग्दर्शक नहीं हो सकता है।

15. जोखिम मूल्य मॉडल के साथ उक्त दो मुद्दों के अलावा, डेटा होराइजन का भी एक मुद्दा है। जहाँ तक बाजार जोखिम की बात है उसके लिए उच्च फ्रिक्वेंसी डेटा उपलब्ध है, अतीत से अल्पकालिक होराइजन पर निर्भरता भ्रमकारी हो जाती है क्योंकि यह तनाव अवधि

के डेटा को समाहित करने में विफल हो सकती है। मान लो ऐसे डेटा को इकट्ठा भी कर लिया जाए जैसाकि संकट के बाद बीसीबीएस के संशोधित बाजार जोखिम ढांचे के अंतर्गत अब किया जाना जरूरी है, बहुत अधिक सटीकता के रूप भविष्य का अनुमान लगाना असंभव है क्योंकि इसकी भविष्यवाणी करना और मानव व्यवहार को मॉडल रूप देना कठिन है। ऋण जोखिम मॉडलिंग में, चूक के पर्याप्त डेटा की कमी का एक अतिरिक्त मामला है।

16. साक्ष्य रूप में मौजूद सभी अंतर्निर्हित कमजोरियों के बावजूद, जोखिम मॉडल पर बहुत अधिक आस्था और अत्यधिक निर्भरता जोखिम प्रबंधन के लिए विनाशकारी रही है। अपने मुख्य निवेश कार्यालय (सीआईओ) में जे पी मार्गन डेरिवेटिव हानियों की हाल की गाथा ऐसे मॉडलों की अविश्वसनीयता और जटिल डेरिवेटिव उत्पादों के साथ जुड़े जोखिमों का सही-सही अनुमान लगाने में उनकी असमर्थता तथा जोखिम गवर्नेंस की विफलता का एक दूसरा अनुस्मारक है। यह हास्यास्पद है कि बैंकों को जोखिम से बचाने और इनको हानियों से सुरक्षित करने के लिए किए गए कार्य-व्यापारों को स्वयं ही हानियों से गुजरना पड़ा। यह सुशात है कि फर्म द्वारा नियोजित नया जोखिम मूल्य, जो संकट को भली-भाँति पार कर गया, दुर्घटना के लिए कम-से-कम आंशिक तौर पर जिम्मेदार हैं। यह सुस्पष्ट है कि हम उच्चकोटि के गणित से चौंधिया गए हैं और हमने इस उच्चकोटि की तुलना गुणवत्ता से करके गलती की है। यह गलती संख्यात्मक वित्त को भौतिकी के स्तर का दर्जा देने के कारण हुई है - यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्री भौतिकी के प्रति ईर्ष्या से ग्रस्त होते हैं। भौतिकी और संख्यात्मक वित्त के बीच बहुत अधिक मूलभूत अंतर है। भौतिकी में निःसंग के उन नियमों का अध्ययन किया जाता है जो ब्रह्मांड को संचालित करते हैं। वस्तुओं के विशिष्ट भौतिक गुण (अर्थात स्थिति, आवेग, तापमान आदि) होते हैं और ब्रह्मांड प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार कार्य करता है। भौतिक गुणों का कोई पर्यवेक्षण अथवा मापन इनमें परिवर्तन नहीं ला सकता है यदि ऐसा होता है तो यह ऐसे भविष्यवाणी योग्य तरीके से होता है कि मापांकन से पहले गुण का वास्तविक मूल्य पूरी सटीकता के साथ जाना जा सकता है। भौतिकी का अति सूक्ष्म संसार (क्वांटम मैकेनिक्स) बहुत अधिक जटिल है और इस संबंध में सच्चाई के स्वरूप के बारे में कोई पूर्व निश्चित धारणाएं नहीं हैं। इसके बावजूद, सूक्ष्म संसार पूर्व निश्चित तरीके से परिभाषित नियमों के अनुसार विकसित हो रहा है। लेकिन, मापांकन अंतर्कीयाओं के दौरान परिणाम पूर्व निश्चित नहीं होते हैं परंतु वे एक संभावना संवितरण का अनुगमन करते हैं जो स्थिर है।

दूसरी तरफ, वित्त में, वित्तीय बाजारों के ऐसे कोई नियम नहीं होते हैं। अस्तियों का 'मूल्य' वित्तीय लिखतों का अंतर्निहित गुण नहीं होता है और आर्थिक एजेंट वित्तीय प्रणाली के बाह्य पर्यवेक्षक नहीं होते हैं। वास्तव में यह मानव मस्तिष्क होता है, इसकी महत्वाकांक्षा, प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, धुन और लोभ होता है जो आर्थिक एजेंटों के कार्यों को प्रेरित करते हैं और यहीं वो कार्य होते हैं जो वित्तीय लिखतों के मूल्य को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार, भौतिकी के असमान, वित्त में ये पर्यवेक्षक ही होते हैं जो वित्तीय लिखतों का मूल्य निर्धारित करते हैं। इसका कोई एक मूल्य नहीं होता है, इसका निर्धारण आर्थिक एजेंटों की सामूहिक मानसिकता के द्वारा होता है और इसीलिए ऐसा मूल्यन चरम स्थिति में होता है जब सुखाभास या निराशा की सामूहिक भावना होती है। इसलिए वित्तीय जोखिम मॉडलिंग भौतिकी की मॉडलिंग की तुलना में ज्यादा जटिल है। जैसा कि पेबल ट्रियाना ने अपनी पुस्तक में लिखा है<sup>4</sup> ‘जब वित्तीय अस्तियों की बात आती है तो ऐसा कोई अपरि वर्तनीय नियम नहीं है....। वित्त में कोई सत्य नहीं होता है। मानव की उपयोगिता ग्रहण संबंधी अनिश्चितता के कारण हर पल एक नई सच्चाई पैदा होती है।’

17. जोखिम मॉडलिंग में अभूतपूर्व परिवर्तन के लिए उक्त चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। जोखिम मॉडल आउटपुट को संपूरित करने के लिए स्ट्रेस परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण पर बढ़ रहा जोर सही है ताकि दुर्लभ किंतु सत्याभाषी घटनाओं से उत्पन्न जोखिम की गणना की जा सके और वित्तीय संस्थाओं को पुनर्जीवन के लिए तैयार किया जा सके। जबकि ‘अति सूक्ष्म’ परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से यह एक सुधार है, मॉडलिंग प्रणालीगत जोखिम ज्यादा गहन हैं क्योंकि ये सहभागी आर्थिक एजेंटों की अनुक्रियाओं के परिणामस्वरूप प्रणाली के अंतर्गत अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न हुए हैं। इस अंतर को संकट के पश्चात बनाए गए प्रणालीगत नियामकों द्वारा संभवतः भरा जा सकता है : भारत में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, अमरीका में वित्तीय प्रणाली निगरानी परिषद, बिट्रेन में वित्तीय नीति समिति और यूरोप में यूरोपियन प्रणालीगत जोखिम बोर्ड आदि। प्रणालीगत जोखिम विनियामकों के पास उपलब्ध वित्तीय डेटा को प्रशस्त करने और गहन बनाने के अंतरराष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। प्रणालीगत जोखिम के मॉडल<sup>5</sup> को बनाने के लिए आर्थिक और वित्तीय प्रणाली के व्यवहारगत नियमों और तुलनपत्र के दबावों का प्रयोग करके इन आंकड़ों को संभवतः समेकित किया जा सकता है। प्रणालीगत

जोखिम मॉडलिंग के लिए ये दिन बहुत ही शुरुआती हैं और समय बीतने के साथ इसमें काफी अधिक सुधार होगा। इस बीच में, नियामक के लिए एक अतिरिक्त पूँजी अपेक्षा और समाधान तंत्र बनाया गया है ताकि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं और चक्रीय अनुकूलता के मामलों के समाधान हेतु चक्रीय पूँजी आवश्यकताओं से निपटा जा सके। वित्तीय बाजारों की अंतर्संबद्धता के कारण उत्पन्न हुए प्रणालीगत जोखिम को कम करने के लिए ओवर दि काउंटर डेरिवेटिव से केंद्रीय काउंटर पार्टी में अंतरण की रूपरेखा बनाई गई है।

18. तमाम आलोचनाओं और कमियों के बावजूद, संख्यात्मक मॉडल के जोखिम प्रबंधन ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं लेकिन निर्णय लेने में उन्हें एक पूरक के रूप में समझा जाना चाहिए। प्राथमिक रूप से, गुणवत्ता निर्णय, अनुमान और सामान्य ज्ञान को जोखिम से निपटने के मार्ग में निर्देशी कारक समझा जाना चाहिए। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि यह महसूस कर लिया जाए कि जोखिम मॉडल में मापे जाने के परे भी ऐसे जोखिम हैं। ये हैं: अनिश्चितताएं (अर्थात् अज्ञात जोखिम जिनकी पहचान की जा सकती है और जिनका मापांकन नहीं किया जा सकता है जैसे ख्याति जोखिम) और अज्ञात जोखिम (इस जोखिम के होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है जैसे 9/11)। जबकि अज्ञात जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा उपाय करना कठिन कार्य है, अनिश्चितता से निपटने का सर्वोत्तम तरीका इसकी विद्यमानता और इसको संख्यात्मक रूप देने संबंधी जानकारी रखना है तथा तदनुसार कार्रवाई करके निरोधात्मक उपाय करना है। वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के समूह की रिपोर्ट ‘हाल के बाजार उथल-युथल के दौरान जोखिम प्रबंधन व्यवहारों पर विचार’, (मार्च 2008) में पुष्टि की गई है कि वही वित्तीय संस्थाएं संकट की स्थिति में बेहतर रहीं जो, अन्य बातों के साथ-साथ, जोखिम प्रबंधन तथा प्रबंधन रिपोर्टिंग और व्यवहारों की जानकारी से पूर्ण तथा उनके प्रति अनुक्रियाशील थीं। गुणवत्ता तथा संख्यात्मक विश्लेषण के मिश्रण ने उभरती दशाओं के प्रबंधन के लिए उच्च स्तर की अंतर्वृष्टि और निरंतर सूचनाएं प्रदान कीं जिससे फर्म को नए अवसरों और जोखिमों का प्रभावपूर्ण तरीके से सामना करने की सामर्थ्य प्राप्त हुई। यह स्पष्ट है कि ऐसी फर्में संख्यावाली जोखिम मॉडल पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहीं।

19. इससे सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित करने में नियामकों/पर्यवेक्षकों की भूमिका का प्रश्न सामने आया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें सुनिश्चित करना है कि बैंकों द्वारा प्रयुक्त जोखिम मॉडल सुदृढ़ हैं। बासेल II के उन्नत दृष्टिकोण के कार्यान्वयन

<sup>4</sup> ट्रियाना, (2009), लेक्चरिंग बर्ड्स ऑन फ्लाइंग, जॉन विले एंड संस, आईसी।

<sup>5</sup> हल्डने, एंड्रयू जी (2012), टेल्स ऑफ द अन्यक्षेक्टड।

की जिम्मेदारी बैंकों द्वारा आंतरिक मॉडल के उपयोग को अनुमोदित करने के पहले नियामकों पर डाली गई है। अनिवार्यतः इसका मतलब है कि नियामक जोखिम मॉडलिंग के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करें और इस प्रकार ‘अंतिम उधारदाता के जोखिम मॉडलर’ बन जाएं<sup>6</sup>। इससे जोखिम प्रबंधन में एकरूपता आएगी जबकि तर्कसंगत बात यह है कि इससे विजातीयता और अधिक वांछनीय होगी क्योंकि जोखिम प्रबंधन के प्रति एक समान दृष्टिकोण वित्तीय बाजार में सह संबंधों को बढ़ाकर बाजार उतार-चढ़ाव को गति दे सकता है, जिसका परिणाम व्यापक प्रणालीगत जोखिम हो सकता है। इस समय इस विभ्रम का कोई समाधान नहीं नजर आ रहा है।

20. नियामक निम्नगामी प्रतिस्पर्धी दबावों को रोकने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। अल्पकालिक कार्यनिष्पादन अर्थात तिमाही, छमाही अथवा वार्षिक पर बहुत अधिक बल दिए जाने के कारण बैंकों पर प्रतिस्पर्धा का बहुत अधिक दबाव होता है जिससे वे जोखिमपूर्ण व्यवहार करने लग जाते हैं (चाहे जोखिम मॉडल में हेरफेरा करके भी) यद्यपि वे इस जोखिम को पूरी तरह जानते हैं जिसे वे कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में मानो बैंक चुपके से यह कामना रखते हैं कि नियामक आगे आएं और जोखिमपूर्ण गतिविधियों को खुलकर रोकें। मैं पॉलसन की पुस्तक ‘ऑन दि ब्रिंक’ से उद्भूत करना चाहता हूँ जो उस समय अमरीका में ट्रेजरी सेक्रेटरी थे जब संकट का विस्फोट हुआ था। 26 जून 2007 को रात्रि के भोजन के समय की बात है (वित्तीय तूफान आने के ठीक पहले) जिसमें स्वयं पॉलसन और वाल स्ट्रीट की कुछ सबसे बड़ी फार्मों के प्रमुख उपस्थित थे:

‘सभी (अर्थात् सभी सीईओ) बाजार में अत्यधिक जोखिम लेने से चितिंत थे और हामीदारी मानकों के क्षरण से भयभीत थे। बैंकरों ने सभी कोवेनेंट - लाइट और ब्रिज कर्जों के बारे में शिकायतें कीं जब उन्होंने प्रतिस्पर्धी दबावों के कारण विवशता महसूस की। मुझे जेमी डिमन, जेपी मार्गन, अध्यक्ष और सीईओ को यह कहते हुए स्मरण है कि ऐसे कर्जों का कोई तुक नहीं है। स्टीव स्वार्जमैन, जो एक शक्तिशाली निजी इक्विटी फर्म ब्लैंकस्टोन के सीईओ थे, ने स्वीकार किया कि उन्हें आकर्षक शर्तें मिल रही हैं तथा उन्होंने कहा कि वह आकर्षक धन को वापस करने के कारोबार में नहीं हैं।

सिटीग्रुप के सीईओ चक प्रिंस ने पूछा कि प्रतिस्पर्धी दबावों को देखते हुए क्या कुछ जोखिमपूर्ण व्यवहारों को कम करने में नियामकों की कोई भूमिका नहीं थी। मूल रूप से उन्होंने पूछा “क्या आपके पास

<sup>6</sup> डेनीलसन, जॉन, ‘ब्लेम दि मॉडलर, जार्नल ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेबिलिटी 4 (2008)।

ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमें इन सभी जोखिमों को न उठाने के लिए आदेश दे सकें”?

उसके कुछ ही समय पश्चात, प्रिंस को यह कहते हुए उद्भूत किया गया ‘जबतक संगीत बज रहा है, आपको उठ खड़ा होना होगा और नृत्य करना होगा’।

21. हाल का लिबोर कांड इस संबंध में एक मामला है। यह बोध कि लिबोर जो सभी सूचकांकों का जनक है, दूसरे दिन तक अतिपावन समझा जाता था और लगभग 800 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के वित्तीय लिखतों (इस पृथ्वी पर सभी राष्ट्रों की जीडीपी का 11 गुना) के मूल्यन के लिये प्रयोग किया गया था, यह बहुतों के लिए एक आघात के रूप में था। इस उप कथा में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के बुरे प्रभावों तथा विनियामी निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है (अर्थात् इस मामले में दर निर्धारण प्रक्रिया की निगरानी)। अब मैं जोखिम प्रबंधन के संबंध में गवर्नेंस के मुद्दे पर ध्यान चाहूँगा।

### III. कार्पोरेट और जोखिम गवर्नेंस प्रबंधन

22. इतिहास यह साबित करने के लिए ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है कि कमजोर कार्पोरेट गवर्नेंस विशेष रूप से कमजोर जोखिम गवर्नेंस प्रणाली बार-बार वित्तीय संकटों का एक प्रमुख कारक रही है। वैश्विक वित्तीय संकट और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अत्यधिक जोखिम लेने से जुड़े सबको, बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की कमजोर निगरानी, जोखिम निर्माण की अपर्याप्त समझ और अतार्किक मुआवजा पैकेज ने एक बार फिर कार्पोरेट तथा जोखिम गवर्नेंस के मुद्दों को सामने ला दिया है।

23. जोखिम गवर्नेंस को समग्र कार्पोरेट गवर्नेंस ढांचे के अंतर्गत एक घटक के रूप में वर्णित किया जा सकता है और इसे जोखिमों के व्यापक मूल्यांकन तथा प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने हेतु बनाए गए एक समन्वित ढांचे के रूप में परिभाषित किया गया है। एक प्रभावी जोखिम गवर्नेंस ढांचा सुनिश्चित करता है कि कोई फर्म चयनित जोखिम लेने वाले ढांचे के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम है।

### IV. बैंकों में जोखिम गवर्नेंस क्यों महत्वपूर्ण है?

24. बैंक अति विशिष्ट होते हैं। मध्यस्थ के रूप में वे जोखिम रूपांतरण का कार्य करते हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के पास जोखिमों का भंडार इकट्ठा हो जाता है। इसके अलावा, उधार देने के लिए जमाओं को स्वीकार करने का बैंकों का कारोबारी मॉडल बहुत अधिक लीवरेज का कारण बनता है (1995-2010 के दौरान बैंकों का

लगभग 18 गुना लीवरेज रहा, जबकि गैर-वित्तीय फर्मों<sup>7</sup> का 3 गुना लीवरेज था।) चलनिधि जोखिम भली प्रकार पूँजीकृत बैंकों के लिए भी नाजुक हो सकते हैं, यह एक ऐसा सबक हैं जो वैश्विक संकट के दौरान प्रभावशाली रूप में देखने में आया।

25. बैंकिंग कारोबार बहुत अधिक कृत्रिम और जटिल हो गया है। जोखिम भी कृत्रिमता और जटिलता के अनुपात में बढ़ा है। बैंकों के जोखिम लेने के व्यवहार में, प्रणालीगत जोखिम में योगदान करने तथा उसे बढ़ाने और परिणामतः संक्रमण की क्षमता है। इसका वित्तीय और आर्थिक दुर्बलता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है जैसाकि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान और उसके पश्चात देखा गया।

26. एकल कारोबारी मॉडल और वित्तीय प्रणाली में उनकी विशिष्ट भूमिका को देखते हुए बैंकों के लिए सुदृढ़ आंतरिक गवर्नेंस आवश्यक है साथ ही बोर्ड के लिए यह जरूरी है कि वे जोखिम के मूल्यांकन, प्रबंधन और उसे कम करने पर अधिक बल दें। बैंक जन विश्वास की नींव पर कार्य करते हैं और इस विश्वास में थोड़ी सी भी कमी बैंक पर से विश्वास उठा सकती है और परिणामतः वे विफल हो सकते हैं।

## V. गवर्नेंस विफलता में वैश्विक वित्तीय संकट से सबक

27. वैश्विक संकट ने हमें सिखाया है कि कोई भी वित्तीय संस्था सभी संभावित संकटों से प्रतिरोधी नहीं हो सकती है और कोई संख्यावाची मॉडल सभी जोखिमों को पूरी तरह से समाहित नहीं कर सकता है। इस ज्ञान ने जोखिम संस्कृति, जोखिम सजगता और मूल्यांकन को मजबूत करके जोखिम गवर्नेंस को सशक्त बनाने पर बल देने के लिए प्रोत्साहित किया है। गवर्नेंस को केंद्र बिंदु पर लाया गया है और गवर्नेंस ढांचे में अंतरों तथा कमियों को दूर करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, जो अनुमानतः वित्तीय संकट को बढ़ाने वाले रहे थे। वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट, ग्रुप ऑफ 30 रिपोर्ट, वाकर्स-रिपोर्ट आदि इस दिशा में कुछ ऐसे ही उपाय हैं। बासेल समिति ने भी 2010 में बैंकों में कार्पोरेट गवर्नेंस के लिए संशोधित ढाचा जारी किया है।

28. वैश्विक संकट को बढ़ाने में गवर्नेंस ढांचे के अंतरालों द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के समूह

ने अपनी रिपोर्ट, ‘रिस्क मैनेजमेंट लैसंस फॉम दि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसेज ऑफ 2008’ में पाया कि फर्मों के जोखिम प्रबंधन व्यवहारों में सुधार की हाल की प्रगति के बावजूद, गवर्नेंस, प्रोत्साहन संरचना, सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर और आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों को दूर करने के लिए काफी अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है कि प्रभावित संस्थाओं का निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन अपनी-अपनी संस्थाओं में जोखिम को पहचानने और उसके अत्यधिक निर्माण अथवा जोखिम पर उनके योगदान तथा प्रणाली में लीवरेज के असमानुपातिक स्तर पर कोई सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहे। बैंकों / अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिए जा रहे जोखिमों तथा उनके निदेशक मंडल के विचाराधीन स्तर पर लिए जाने वाले जोखिमों के बीच एक सामान्य असंबद्धता रही।

29. सुदृढ़ गवर्नेंस प्रणाली ने संकट के दौरान सफल फर्मों को अन्यों से अलग किया। जोखिम गवर्नेंस की अच्छी प्रणालियों वाले संगठनों ने लोचपूर्ण<sup>8</sup> ढंग से प्रतिक्रिया की और अपने संकट को दूर कर सके। ऐसा लगता है कि कोई भी वित्तीय संस्था संकट की विशालता का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकी - जिस प्रकार से इन संस्थाओं ने प्रतिक्रिया की और किस तरीके से उनके परिणाम प्रभावित हुए यह, बड़े हिस्से में, उनके आंतरिक जोखिम गवर्नेंस ढाचे की शक्ति और संरचना पर निर्भर रहा। संस्थाओं के बोर्ड तूफानी मौसम का सामना करने के लिए बेहतर स्थिति में थे, उन्हें सामान्यतः समय पर, पूर्णतः के निकट, और उद्यम व्यापी जोखिम सूचनाएं प्राप्त हुईं जिससे वे जोखिम को पहले से कम करने के संबंध में नाजुक निर्णय ले सके - अर्थात जब आस्ति मूल्य नीचे गिर गए और निधियों के बाजार आधारित स्रोत पहुँच से बाहर हो गए<sup>9</sup>।

30. तीस का समूह (जी 30) की रिपोर्ट, ‘टुवार्ड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ फायरेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कहा गया है कि प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं को विवेकपूर्ण तरीके से संचालित करने और निगरानी करने के लिए प्रबंधन दल, निदेशक मंडल, नियामक और पर्यवेक्षक तथा शेयरहोल्डर सभी अपनी-अपनी भूमिका में असफल रहे।

<sup>8</sup> वरिष्ठ पर्यवेक्षक समूह (2008), ‘ऑब्जरवेशंस ऑन रिस्क मैनेजमेंट प्रेक्टिसेज ड्यूरिंग दि रिसेट मार्केट टर्बुलेंस’।

<sup>9</sup> विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (2010), ‘बैंक गवर्नेंस : लेसंस फ्रॉम दि फायरेंशियल क्राइसेज नोट संख्या 13।

<sup>7</sup> करुआना, जैम (2012), ‘शेयर होल्डर वैल्यू एंड स्टेबिलिटी इन बैंकिंग: इज देयर कंफिल्क्ट’?

31. गवर्नेंस की विफलता, जिसके कारण वैश्विक वित्तीय संकट आया, को व्यापक तौर पर बोर्ड स्टरीय निगरानी में कमज़ोरी के रूप में वर्णित किया जा रहा है। बोर्ड फर्मों की जोखिम लेने की इच्छा में सक्रिय तौर पर संलिप्त नहीं रहे। बोर्ड को अपूर्ण जोखिम की जानकारी ने संस्था के फर्म व्यापी जोखिम प्रोफाइल को पूरी तरह से समझने / मूल्यांकन करने तथा बोर्ड स्तर पर इस संबंध में प्रभावी निर्णय लेने से रोका जिससे जोखिम प्रबंधन ढाँचे से संबंधित आत्मतुष्टि की भावना को जन्म मिला। निदेशकों, विशेष रूप से स्वतंत्र निदेशकों के बीच भी विछित तरीके से जोखिम को समझने अथवा उसके प्रति प्रतिक्रिया करने की विशेषज्ञता की मौलिक कमी रही।

32. गवर्नेंस व्यवहारों को वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर इसी प्रकार की कमज़ोरियों का शिकार होना पड़ा। वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम<sup>10</sup> को पहचानने, प्रबंध करने और रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक प्रणालियां अपनाने तथा उनका तालमेल करने में विफल रहा। तेजी से उभरते तुलन पत्रों के कारण उत्पन्न समग्र जोखिम के स्तर और स्वरूप को कैचर करने में प्रबंधन सूचना प्रणाली में भी कमियां देखी गईं। इसके अलावा, जोखिमों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया जिसका परिणाम पूँजी के अनुपयुक्त आबंटन, अप्रत्याशित घटनाओं की अपर्याप्त तैयारी के रूप में दिखा जिसके फलस्वरूप संकट में बढ़ोतरी हुई।

33. असंतुलन का दूसरा क्षेत्र जोखिम पुरस्कार और पारश्रमिक ढाँचा था। मुआवजा पैकेज ने, आसन्न लक्ष्य के रूप में अल्पकालिक लाभ उद्देश्य के साथ, जोखिम लेने के व्यवहार को प्रोत्साहित किया जो संगठन की दीर्घकालिक वित्तीय हालत की कीमत पर था। मुआवजा पैकेज में उन प्रतिकूल परिणामों अथवा हानियों को रोकने या कम करने के लिए उपयुक्त सुरक्षा उपाय शामिल नहीं किए गए जो हानियां अविवेकपूर्ण अथवा अत्यधिक जोखिम लेने से दीर्घकाल में हो सकती थीं और संगठन की सुरक्षा और सुदृढ़ता को खतरे में डाल सकती थीं।

34. संकट ने उद्यम व्यापी जोखिम निर्णय लेने की प्रक्रिया के अभाव पर भी प्रकाश डाला। जोखिम प्रबंधन ढाँचा उद्यम स्तर के बजाय सिलोस अर्थात् पृथकता पर आधारित था, इस प्रकार यह व्यापक उद्यम तस्वीर से वंचित रहा, साथ ही विभिन्न संगठनों के बीच जोखिमों के आपसी आदान-प्रदान की समझ से भी वंचित रहा। चूंकि जोखिम की समग्र तस्वीर बोर्ड अथवा उच्च प्रबंधन के

पास उपलब्ध नहीं थी, परिणामी नियंत्रणों और मानदंडों को घटाना भी अपर्याप्त तथा अप्रभावी साबित हुआ जिसने प्रभावी जोखिम प्रबंधन को रोका।

## VI. सुदृढ़ जोखिम गवर्नेंस ढाँचा बनाना - भावी मार्ग

35. यह एक आगे की सोच है कि जोखिम गवर्नेंस के लिए साकल्यवादी दृष्टिकोण की जरूरत है और जोखिम का मूल्यांकन शीर्ष से होना चाहिए। निगरानी तथा निर्णय निर्माण में बोर्ड की दक्षता बढ़ाने के लिए सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म द्वारा समर्थित शक्ति संपन्न प्रबंधन सूचना प्रणाली एक आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की कौशल संपन्नता और उनका अनुभव बोर्ड की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन, बोर्ड के लिए प्रभावी और व्यापक तरीके से जोखिम की रिपोर्टिंग को सुविधाजनक बनाता है जिससे अंततः पारदर्शिता बढ़ती है और सही निर्णय लिए जाते हैं। प्रबंध सूचना प्रणाली ढाँचे को समर्थन देने के लिए सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली एक आवश्यक शर्त है क्योंकि बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन को प्राप्त होने वाली जोखिम सूचनाओं की गुणवत्ता बढ़े पैमाने पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों की गुणवत्ता और सुदृढ़ता पर निर्भर होती है<sup>11</sup>।

36. संस्था के लिए जोखिम लेने की क्षमता निर्धारित करने के अलावा, बोर्ड को समुचित जोखिम रणनीति भी बनानी होती है और सुनिश्चित करना होता है कि इस रणनीति को संगठन में समग्र रूप से अपनाया जाए। इससे जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का समग्र कारोबारी रणनीति के साथ तालमेल बनेगा, पदानुक्रम में भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की सही परिभाषा होगी, जवाबदेही स्थापित होगी तथा संचार और प्रशिक्षण में परिवर्तन को बल मिलेगा। बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन की निगरानी को अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा सूचित गैर-कार्यपालक निदेशकों के प्रभावी नेतृत्व द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। बोर्ड को जोखिम के मामलों में बहुत अधिक गंभीरता से कार्य करना चाहिए तथा कारोबार द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख जोखिमों की गहरी समझ होनी चाहिए।

<sup>10</sup> दि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनैशनल फाइनैंस कार्पोरेशन (2010), 'बैंक गवर्नेंस : लैसंस फ्राम दि फाइनैशियल क्राइसेज', नोट संख्या 13।

<sup>11</sup> तीस का समूह, 'ट्रिवर्ड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ फाइनैशियल इंस्टीट्यूशन'।

37. प्रभावी जोखिम गवर्नेंस की भी यह मांग है कि प्रत्येक निदेशक को बैंक द्वारा सामना किए जा रहे जोखिमों के आकार का पता होना चाहिए। जब निदेशकों के पास वित्तीय विशेषज्ञता होती है तो वे बोर्ड में मूल्य योजन करते हैं, जोखिम के आधारभूत तत्वों तथा तकनीकी से वाकिफ होते हैं और वे कार्यपालकों के साथ गतिशीलता का निर्वाह करने में समर्थ होते हैं।

38. समग्र जोखिम गवर्नेंस ढांचे में बासेल स्तर की जोखिम समितियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। फर्म की रणनीति-जोखिम प्रोफाइल की निरंतर आधार पर निगरानी करने के अलावा, ऐसी समितियां फर्म की समग्र जोखिम लेने की क्षमता को परिभाषित करने; फर्म की जोखिम लेने की सीमा से ऊपर बढ़े-लेन देनों को अनुमोदित करने; वैयक्तिक कारोबारों में प्रयोग के लिए सीमित स्ट्रक्चरों और जोखिम नीतियों को स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार होंगी।

39. मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की उपस्थिति से जोखिम प्रबंधन ढांचे के मजबूत होने की आशा है। सीआरओ की स्वतंत्रता, जिसमें उसके पास निर्णयों को प्रभावित करने का आवश्यक कद हो, जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और जोखिम प्रबंधन से संबंधित निर्णयों में भी इस पद की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी। सीआरओ को प्रत्यक्ष रूप से सीईओ और बोर्ड को रिपोर्ट करना होगा और सभी जोखिमों, जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण कार्यों के लिए जवाबदेह बनना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण अपेक्षा कारोबार रणनीति और मुआवजे के साथ जोखिम का समन्वयन है। जोखिम और जोखिम पर प्रतिफल को किसी कार्यनिष्पादन मानदंड का मूल घटक होना चाहिए और इसको प्रोत्साहन और मुआवजा योजना में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए। मुआवजे को वास्तविक कार्य-निष्पादन के औपचारिक रूप के अनुरूप बनाया जाना चाहिए जैसे स्कोरकार्ड में और अधिक दुःसाध्य जोखिम आधारित उपाय करने के माध्यम से। इससे कार्य निष्पादन की अवधि और भी बढ़ जाएगी तथा आस्थगित मुआवजा बढ़ जाएगा।

40. पृथक-पृथक सिलोस में जोखिम डेटा का विखंडित संगठन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को धीमी करता है और नई नियामक अपेक्षाओं के प्रति रिस्पांड करने में रुकावट डालता है। वित्तीय संकट ने पर्यवेक्षकों और बाजार सहभागियों दोनों को जोखिम डेटा से समन्वित दृष्टिकोण की ओर जाने के लिए प्रेरित किया है, जिससे संगठन में सिलोस में कमी आई है। डेटा मॉडल, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को समन्वित करके ही कोई बैंक डेटा गुणवत्ता के मामले में उच्च कार्यनिष्पादन प्राप्त कर सकता है।

41. जोखिम प्रबंधन प्रणाली को जोखिम मॉडल जैसे जोखिम मूल्य की तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। तनाव परीक्षण और परिदृश्य विश्लेषण को वास्तविक प्रभावी प्रबंधन उपकरण के रूप में स्थापित किए जाने की आवश्यकता है और इसे विभिन्न कारोबारों, जोखिम के प्रकारों तथा अस्ति वर्गों में समन्वित और मानकीकृत किया जाना चाहिए।

## VII विनियमों को पुनः बनाया जाना - प्रभाव

42. संकट के दौरान विनियमों में पाए गए अंतरों को दूर करने तथा वित्तीय प्रणाली को और लोचपूर्ण बनाने के लिए विनियामक ढांचे की बढ़े पैमाने पर जांच की गई है। नए विनियमों में, जिन्हें बासेल III कहा जाता है, फर्म विशिष्ट और व्यापक रूप से प्रणालीगत जोखिमों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। ये मानदंड पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा को बढ़ाने, चलनिधि जोखिम प्रबंधन, मूल्यन व्यवहारों, चक्रीय अनुकूलता के मामलों से निपटने तथा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकिंग समूहों के साथ-साथ प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के लिए संवर्धित समाधान तंत्र से संबंधित हैं। इसमें मुआवजा नीति, तनाव परीक्षण, पारदर्शिता को बढ़ाने से संबंधित प्रकटन तथा केंद्रीय समाशोधन और निपटान प्रणाली आदि में अंतरण के लिए ओटीसी डेरिवेटिव को प्रोत्साहित करके वित्तीय बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को घटाना भी शामिल किया गया है।

43. नए विनियमों ने इक्विटी पूंजी की आवश्यकता को काफी अधिक बढ़ा दिया है। जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में 2 प्रतिशत की न्यूनतम इक्विटी पूंजी की आवश्यकता से तुलना करने पर, बासेल III की नई व्यवस्था के अंतर्गत 2.5 प्रतिशत के पूंजी कर्जवेशन बफर सहित 7 प्रतिशत इक्विटी पूंजी की शर्त रखी गई है। इसके अलावा, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की आवश्यकता है जिसे कर्तिपय दशाओं में बनाए जाने की जरूरत होगी और विश्व की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के लिए अतिरिक्त पूंजी की भी आवश्यकता होगी। वित्तीय प्रणाली में जोखिमों को रोकने के लिए तथा इसे और अधिक लोचपूर्ण बनाने के लिए उच्च इक्विटी पूंजी को शामिल किया गया है। पूंजी की उच्च आवश्यकताओं के साथ-साथ, नए विनियामी ढांचे में जोखिम कवरेज विशेष रूप से पूंजी बाजार से संबंधित गतिविधियों, व्यापारिक बहियों, प्रतिभूतिकरण उत्पादों, ओटीसी डेरिवेटिव और रिपो पर काउंटर पार्टी क्रेडिट जोखिम को भी व्यापक बनाया गया है। इन सबका परिणाम बैंकिंग क्षेत्र के लिए काफी अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी।

44. अंतरराष्ट्रीय तौर पर, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी की इतनी बढ़ी राशि को जुटाने की संभावना संबंधी चिंताएं हैं तथा ऐसी बढ़ी हुए पूंजी की आवश्यकता का उत्पाद वृद्धि और बैंकों की लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ सकता है। मैं इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगा।

45. पूंजी विनियमन का समष्टि आर्थिक प्रभाव इस संभावना के कारण हो सकता है कि पूंजी जुटाने की उच्च लागत को देखते हुए बैंक या तो उधार देने पर ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं या उधार की राशि को बढ़ा सकते हैं। बीआईएस द्वारा किए गए अध्ययनों में शामिल किए गए लगभग 100 उद्दीपनों से पता चलता है कि वैश्विक सामान्य इक्विटी पूंजी अनुपात को उस स्तर पर, जिससे सहमति प्राप्त न्यूनतम और पूंजी कन्वरजन बफर की आवश्यकता (अर्थात इसे 1.3 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा) पूरी होगी, ले जाने का परिणाम आधार भविष्यवाणियों की तुलना में जीडीपी में अधिकतम 0.22 प्रतिशत की गिरावट आएगी ऐसा हर 35 तिमाहियों के पश्चात घटित होगा। वृद्धि दर के अनुसार, इस समय के दौरान वार्षिक वृद्धि आधारभूत स्तर से नीचे अर्थात् 0.03 प्रतिशत अंक (अथवा 3 आधार अंक) होगी। इसके पश्चात आधारभूत वृद्धि पथ की ओर जीडीपी में सुधार होगा। इन 35 तिमाहियों के दौरान उच्चतर पूंजी का हर प्रतिशत अंक पर अनुमानित अधिकतम जीडीपी का प्रभाव 0.17 प्रतिशत है। वृद्धि और वित्तीय स्थिरता के बीच तालमेल को सहनीयता सीमा के अंतर्गत माना जाता है। यही कारण है कि बासेल III को लंबी अवधि (1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2018 तक) के दौरान लागू किया जाना है जिससे वृद्धि पर प्रभाव कम हो सके और उद्दीपन कार्यान्वयन की समय सीमा को समर्थन करते प्रतीत हों।

46. जहाँ तक बैंकों के लाभ पर प्रभाव की बात है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उच्चतर पूंजी आवश्यकताएं लागत को बढ़ाकर बैंकों के लाभ को प्रभावित करेंगी। बैंकों के पूंजी ढांचे में भी परिवर्तन होगा जिसमें इक्विटी पर पहले से अधिक जोर दिया जाएगा जिसका परिणाम पूंजी की लागत अधिक होगी। आदर्शतन, मोदी गिल्यानी - मिलट सिद्धांत के अनुसार पूंजी ढांचे में परिवर्तन का निधियों की लागत पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इक्विटी के अनुपात में कोई वृद्धि, जो ऋण की तुलना में हमेशा अधिक खर्चाली होगी, को तभी सही-सही समंजित किया जा सकेगा जब दिवालिये होने के कम जोखिम को स्वीकार करते हुए ऋण और इक्विटी दोनों की प्रति

इकाई लागत में कमी आएगी। लेकिन ऐसा आदर्श स्थिति में होगा। वास्तविक संसार में, जहाँ पर ऋण और इक्विटी के बीच विभेदकारी कर संव्यवहार है और जमाराशियों पर भी स्पष्ट और अस्पष्ट गारंटी है, ऋण वित्तीयन को इक्विटी वित्तीयन की तुलना में सस्ता माना जाता है। इसलिए लीवरेज को कम करके पूंजी ढांचे को संशोधित करने के प्रति अनिच्छा दिखती है।

47. इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि उच्चतर पूंजी आवश्यकताओं का बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निवेशक बैंकों के शेयरों के प्रति अनिच्छुक होंगे। दीर्घकालिक दृष्टि से यह तर्क ठीक नहीं है। हमें स्टैंडेलोन आधार पर प्रतिफलों को नहीं देखना चाहिए। यह जोखिम समायोजित प्रतिफल है जो अधिक वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है और यह निवेशकों की प्रत्याशाओं को प्रेरित करता है। बेहतर पूंजीकृत बैंक कम जोखिम के कारण कम लागत पर ऋण और इक्विटी पूंजी दोनों को जुटा सकेंगे।

48. अधिक लीवरेज, जो अल्पकाल में अधिक लाभ दे सकता है, से सुदृढ़ लाभ नहीं होगा। बीआईएस<sup>12</sup> ने अपने हाल के अध्ययन में कहा है कि उन अवधियों के दौरान जिसमें स्टॉक बाजार कार्यनिष्ठादान का सबसे खराब 20 प्रतिशत शामिल है, बैंकों ने अधिकांश अन्य सेक्टरों की तुलना में खराब स्थिति प्रदर्शित की। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि बैंकों के गैर वित्तीय फार्मों की तुलना में लगभग छह गुना से अधिक लीवरेज्ड होने के बावजूद, बैंकिंग में इक्विटी पर औसत प्रतिफल अन्यों की तुलना में बहुत अधिक नहीं रहा है। अध्ययन नमूने में 12.2 प्रतिशत की बैंकों की इक्विटी का प्रतिफल 1999-2009 की अवधि के गैर वित्तीय फार्मों के 11.7 प्रतिशत से बहुत अधिक अलग नहीं रहा है। यह इस कारण से है कि अच्छे समय के दौरान बैंकों के अधिक प्रतिफल उच्च लीवरेज के कारण संकट अवधि के औसत प्रतिफल की तुलना में कम समंजित किए गए। यह बहाना है कि उच्च जोखिम की लागत पर अच्छे समय के दौरान बनाया गया लाभ जोखिम प्रीमियम था और इसे अनुमानित हानि समझा जाना चाहिए ना कि चालू आय जो संवितरणीय थी। इसलिए इक्विटी पूंजी बढ़ाकर लीवरेज कम करने से दीर्घकाल में निवेशक के निवेश भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, यदि ये भाव एक बार सही परिप्रेक्ष्य में सेट हो जाएं तो।

<sup>12</sup> करुआना जैन (2012), ‘शेयरहोल्डर वैल्यू एंड सेबिलिटी इन बैंकिंग: इज देयर ए कंफिलक्ट?’

## VIII. जोखिम प्रबंधन के प्रति रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण

49. अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं जोखिम प्रबंधन के प्रति रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मुक्त बाजारों की आत्म सुधारात्मक प्रकृति में विश्वास की पराकाष्ठा के बाद भी, जो प्रकृति संकट के बाद दिख भी रही है, रिजर्व बैंक ने नवोन्मेष को बढ़ाने और बाजार में नवीन उत्पादों की अनुमति देने में निरंतर जागरूकता पूर्ण दृष्टि बनाए रखी। रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने की बाब्ताओं से दिशानिर्देशित है कि वित्त वास्तविक क्षेत्र से संबंधित होता है और इसमें गतिशीलता स्वमेव नहीं आती है। हमारी अर्थव्यवस्था की प्रकृति को देखते हुए जिसमें आय स्तर, शिक्षा और आधुनिकता के स्तर में काफी अधिक विषमता है तथा समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता है समावेशी बाजार विकास की रणनीति इस प्रकार सोच समझकर बनाई गई है जिससे किसी ऐसी ज्यादती से बचा जा सके जिसके कारण बाजार विफलता की संभावना हो सकती है। नए-नए उत्पाद शुरू किए गए विशेष रूप से वित्तीय बाजार और सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था की तैयारियों के कारण। ये उत्पाद शुरू-शुरू में भली-भांति विनियमित सहभागियों के लिए खोले गए थे और इन उत्पादों के सुस्थापित तथा सुकर होने के बाद ही, अन्य सहभागियों को अनुमति दी गई। केवल बैंक जैसी विनियमित संस्थाओं को ही डेरिवेटिव बाजार में बाजार बनाने की अनुमति दी गई, जबकि अन्य को केवल अपने तुलनपत्र के जोखिमों को बचाने के लिए ऐसे उत्पादों के प्रयोग की अनुमति दी गई, न कि बाजी लगाने के लिए। इस प्रकार बाजारों के खुलाव ने क्रमिक रणनीति का अनुगमन किया है। इसने हमें अच्छी स्थिति में रखा है जिससे बाजार गतिविधियों में कोई बड़ी बाधा नहीं आई है वैश्विक वित्तीय संकट की चरम सीमा पर भी। जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से वित्तीय नवोन्मेष को आसान बनाने में डेरिवेटिव बाजार के नियमन के प्रति सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के कारण, रिजर्व बैंक को जिम्मेदारीपूर्ण नवोन्मेष के लिए 2012 का डफ़ेनॉम पुरस्कार दिया गया है।

50. वित्तीय प्रणाली के विवेकपूर्ण विनियमन के संदर्भ में भी, रिजर्व बैंक ने चक्रीय अनुकूलता और अतर्संबद्धता आयाम दोनों से आए प्रणालीगत जोखिम को सीमित करने का एक सुविचारित दृष्टिकोण अपनाया। चक्रीय प्रतिकूल उपाय 2004 में अपनाए गए जब विशिष्ट क्षेत्रों में 'हीटिंग अप' को देखा गया। जब बाजार में तेजी थी तब पूंजी बाजार, आवास, वाणिज्यिक भूसंपदा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए

जोखिम भारांक और प्रावधानन अनुपात को बढ़ाया गया। इन अनुपातों को अक्टूबर 2008 में घटाया गया जब अर्थव्यवस्था में वैश्विक उथल-पुथल की पृष्ठभूमि में गिरावट शुरू हो गई। ऐसे समष्टि विवेकपूर्ण दृष्टिकोण ने, जो उस समय व्यापक तौर पर प्रचलित नहीं था, घरेलू अर्थव्यवस्था को संकट की पराकाष्ठा के दौरान प्रतिकूल आघातों से बचा लिया। एक तरफ, बैंकों के बीच और दूसरी तरफ, बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बीच अतर्संबद्धता को कम करने के लिए भी कई उपाय किए गए और प्रणालीगत जोखिम के विभिन्न क्षेत्रों के आयात की समस्याओं से निपटने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति जोखिमों पर सीमाएं लगाई गई हैं।

51. बासेल III के दिशा निर्देशों के अनुपालन में भी, हमने एक सतर्कतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है चूंकि न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को बासेल III के अंतर्गत बताई गई सीमा से 1 प्रतिशत अंक अधिक रखा गया है ताकि पूंजी आबंटन प्रक्रिया की संभावित अपर्याप्तताओं और बैंकों में मॉडल जोखिम को भी संबोधित किया जा सके। कार्यान्वयन सारणी को भी मामूली रूप से 9 महीने कम रखा गया है जिसे 31 मार्च 2018 तक अनुपालित किया जाना है जबकि बासेल आवश्यकता को 01 जनवरी 2019 तक अनुपालित किया जाना है।

52. जोखिम प्रबंधन के प्रति रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण पर चर्चा करने के पश्चात, मैं अब भारत में बासेल III के कार्यान्वयन के संदर्भ में कुछ समकालिक मुद्दों तथा कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करना चाहूँगा।

### पूंजी विनियमों को क्यों लागू किया जाए?

53. यह तर्क दिया जा रहा है कि हमारी जैसी उभरती अर्थव्यवस्था, जो न तो प्रत्यक्ष कारण रही और न ही वैश्विक संकट का प्रत्यक्ष शिकार रही, को बासेल III जैसे दुःसाध्य विनियमयन को क्यों अपनाना चाहिए जिसका उत्पाद वृद्धि पर संभवतः नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन मानकों को अपनाने के दो कारण हैं एक, हम अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करने से नहीं बच सकते विशेष रूप से उस समय जब भारतीय बैंक विदेश में अपना कार्य कर रहे हों और हमारे बाजार अंतरराष्ट्रीय सहभागियों के लिए खोल दिए गए हों। दो, यद्यपि हमारी वित्तीय प्रणाली बहुत सामान्य है और इसमें ऐसे अधिक लक्षण नहीं हैं जिनके कारण संकट आया, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के संक्रमण के प्रति सुभेद्य हैं जैसा कि आज हम देख रहे हैं। बासेल III के अंतर्गत बनाई गई उच्चतर सुरक्षा प्रणाली हमारी वित्तीय प्रणाली को आवश्यक आघात सहनीयता प्रदान करेगी।

## चलनिधि वाले मुद्दे

54. बासेल III के अंतर्गत अप्रभारित चल आस्तियों के पूल के रूप में चलनिधि का उच्च स्तर बनाए रखने की आवश्यकता है। यद्यपि भारतीय बैंक सांविधिक चलनिधि अनुपात के अनुपालन में चल आस्तियों का एक बड़ा पूल बनाकर रखते हैं लेकिन उन्हें बासेल III के अंतर्गत तकनीकी रूप से चल आस्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि वे चलनिधि प्रयोजन के लिए बैंकों को आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। बैंकों से अपेक्षा रखना कि वे एसएलआर के अलावा चलनिधि आस्तियां भी रखेंगे, इससे प्रतियोगी रूप में उनके लिए यह स्थिति अलाभकारी होगी। इसलिए हम यह परिचार कर रहे हैं कि किस सीमा तक एसएलआर को चल आस्तियों के रूप में बासेल III की आवश्यकताओं के लिए गिना जा सकता है।

## प्रति चक्रीय पूँजी

55. कारोबार चक्र की अनिश्चितताओं के प्रभाव का सामना करने के लिए प्रतिचक्रीय पूँजी बनाए रखने का विचार सैद्धांतिक तौर पर अच्छा लगता है लेकिन इसके कार्यान्वयन में कठिपय समस्याएं हैं। परंपरागत रूप से जीडीपी की तुलना में कम ऋण अनुपात तथा वित्तीय समावेशन और सापेक्षिक रूप से उच्च वृद्धि की पृष्ठभूमि में हमारी अर्थव्यवस्था के द्वारा अनुभव किए जा रहे संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण, बीसीबीएस ढांचे द्वारा प्रयुक्त 'जीडीपी की तुलना में ऋण अनुपात' वाली उकित भारतीय परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त है। यह सेक्टोरल दृष्टिकोण जिसे हमने अतीत में अपनाया था (अर्थात उच्च वृद्धि वाले सेक्टरों के लिए जोखिम भारांक तथा प्रावधान आवश्यकताओं में परिवर्तन) अधिक उपयुक्त लग रहा है। बासेल ढांचे से विपथन 'अनुपालन अथवा स्पष्टीकरण' ढांचे के अंतरगत ही अनुमति के योग्य है। लेकिन इसका खतरा यह है कि बाजार इस विपथन की अनुपालन के रूप में गलत व्याख्या कर सकता है। इसलिए बासेल द्वारा पीयर ग्रुप समीक्षा के दौरान और बाजार के साथ संप्रेषण का अधिक महत्त्व हो जाता है।

## लीवरेज अनुपात

56. पूँजी पर्याप्तता अनुपात को संपूरित करने के लिए बासेल III द्वारा निर्धारित लीवरेज अनुपात (तुलन पत्रेतर मदों सहित आस्तियों के बही मूल्य की तुलना में टियर I की पूँजी का अनुपात) को बैकस्टॉप व्यवस्था के रूप में रखा गया है। हमारा विचार रहा है कि चूंकि भारतीय बैंकों के लिए एसएलआर की आवश्यकता काफी अधिक है और इसमें बहुत कम जोखिम है, अतः इसको लीवरेज अनुपात के रूप में रखा जाना चाहिए। लेकिन, इसे बीसीबीएस द्वारा स्वीकार नहीं

किया गया है। लेकिन, सहूलियत की बात यह है कि भारतीय बैंकों का लीवरेज अनुपात विचाराधीन स्तर की तुलना में सामान्य है। इसके अतिरिक्त, चूंकि बासेल III चलनिधि ढांचे के अंतर्गत सभी बैंकों को चल आस्तियों को बनाए रखना है, अतः भारतीय बैंकों की भावी प्रतियोगी अलाभ की स्थिति काफी अधिक दूर हो जाएगी।

## बासेल II के उन्नत दृष्टिकोण (कौशल, प्रौद्योगिकी) के कार्यान्वयन की चुनौतियां

57. चूंकि भारत के सभी वाणिज्यिक बैंकों ने मार्च 2009 तक बासेल II के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपना लिया है, उन्नत दृष्टिकोण का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में किया जाना है। चूंकि उन्नत दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी प्रधान है तथा इसके लिए काफी अधिक कुशल कार्यशक्ति की जरूरत है, इससे भविष्य में बैंकों के सामने चुनौतियां आने वाली हैं। उन्नत मॉडलों को बनाने और परीक्षण करने तथा परिदृश्य बनाने के लिए आंकड़ों की उपलब्धता एक दूसरी गंभीर चुनौती होगी।

## मुआवजा नीति

58. अतार्किक मुआवजा नीतियों द्वारा दिया जा रहा विषम प्रोत्साहन, वैश्विक वित्तीय संकट लाने का एक कारक था। मुआवजा नीति ने जोखिमों और दीर्घकालिक परिणामों की सही तरीके से पहचान किए बिना कर्मचारियों को अल्पकालिक लाभ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इन चिंताओं को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय पहल के आधार पर निजी और विदेशी बैंकों के लिए मुआवजा संबंधी व्यवहारों पर दिशानिर्देश जारी किए।

## कंपनी गवर्नेंस

59. बैंकों में कंपनी गवर्नेंस को मजबूत करने और जोखिम प्रबंधन व्यवहारों को समर्थन देने के लिए, रिजर्व बैंक द्वारा प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के रूप में विभिन्न क्षमता निर्माण उपाय किए जा रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए गए कोर बैंकिंग सोल्युशन का अधिकाधिक प्रयोग करने तथा 'अन्य बातों के साथ-साथ' बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने से आए संभावित परिचालनात्मक जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने 2011-17 के लिए एक आईटी विजन दस्तावेज जारी किया है जिसमें जोखिम नियंत्रण आवश्यकता, जोखिम कम करने की प्रणाली, कपट को पकड़ने और रोकने तथा कारोबार निरंतरता योजना पर जोर दिया गया है। उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान और अध्ययन केंद्र (कैफरल) की स्थापना से क्षमता निर्माण के प्रयासों को और विनियमन तथा पर्यवेक्षण में अनुसंधान को बढ़ावा मिलना चाहिए। भारत में विनियमन तथा पर्यवेक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

## वित्तीय स्थिरता समीक्षा तथा रिपोर्ट

60. प्रणाली की दुर्बलताओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए, रिजर्व बैंक आवधिक तौर पर वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और समीक्षा प्रकाशित करता है जिसमें समष्टि विवेकपूर्ण जांच के परिणाम दिए जाते हैं। ये रिपोर्टें विशेष रूप से तेजी से बदलते वैश्विक और घरेलू परिदृश्य के आलोक में हुए प्रणालीगत जोखिम के मूल्यांकन में बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं।

## डायनैमिक प्रावधानन

61. प्रतिचक्रीय प्रावधानों को बनाना विवेकपूर्ण मानदंड हैं जिससे चक्रीय आघातों के विरुद्ध आघात सहनीयता को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। बीसीबीएस, आईएएसबी के साथ परामर्श करके, अनुमानित हानि आधारित प्रतिचक्रीय प्रावधानन कार्य प्रणाली पर कार्य कर रहा है जिसमें समय लगने की संभावना है। भारत में, बैंकों के पास स्टॉक का फ्लोटिंग प्रावधान है जिसे हमने प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी है, प्रणालीगत तनाव की स्थिति को छोड़कर। जबकि फ्लोटिंग प्रावधान प्रतिचक्रीय प्रावधान के प्रयोजन को पूरा करते हैं। इसके प्रयोग को अनुमति देने के लिए एक ढांचा आवश्यक है। आंतरिक उपाय के रूप में, हमने स्पेनिश डायनैमिक प्रावधान प्रणाली के आधार पर एक कार्य प्रणाली विकसित की है जिसे जनता की राय जानने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

## प्रतिभूतिकरण

62. वैश्विक संकट से सीखे गए सबकों के आलोक में, प्रतिभूतिकरण दिशानिर्देश इसलिए यह व्यापक रूप से पुनः बनाए गए हैं ताकि 'आरिजिनेट टु डिस्ट्रीब्यूट' मॉडल को समझाया जा सके और प्रतिभूतिकरण के पश्चात प्रतिभूतिकरण और न्यूनतम धारण अपेक्षा से पहले न्यूनतम धारण अवधि निर्धारित करके निवेश बनाया जा सके।

## वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद

63. संकट के प्रमुख सबकों में से एक यह है कि जोखिम का प्रणालीगत जायजा लिया जाए और जब भी जरूरत हो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए तैयार रहा जाए जिसके लिए विभिन्न नियामकों के बीच गहरे समन्वयन की आवश्यकता है। औपचारिक समन्वयन व्यवस्था के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक वित्तीय स्थिरता और

विकास परिषद (एफएसडीसी) बनाई गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी की एक उप समिति सामान्य समय के दौरान नियामकों के बीच समन्वयन सुनिश्चित करती है।

## होल्डिंग कंपनी बनाना

64. वर्तमान में भारत में अधिकांश वित्तीय समूह बैंकों द्वारा संचालित और बैंक अनुषंगी मॉडल के अंतर्गत संगठित हैं। इस मॉडल के अंतर्गत अनुषंगी बैंकों के कंपनी गवर्नेंस, कार्यनिष्ठादान और पूंजी आवश्यकता के लिए मूल बैंक पर जिम्मेदारी ढाली गई है। इसके अलावा, मूल बैंक को ख्याति जोखिम का बहुत अधिक सामना करना पड़ता है। 'बैंकों के लिए भारत में होल्डिंग कंपनी ढांचा' पर बने कार्य समूह ने प्रमुख वित्तीय संयुक्तों को होल्डिंग कंपनी ढांचे में अंतरण करने की सिफारिश की है ताकि कुछ हद तक इन सीमाओं को दूर किया जा सके। ऐसे अंतरण को आसान बनाने के लिए आवश्यक कानून संशोधन भी करने होंगे।

## वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

65. प्रभावी नियामक प्रणाली के लिए सुदृढ़ और सुस्पष्ट विधायी ढांचा एक प्राथमिक आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में लगभग 60 अधिनियम हैं और अनेक नियम तथा विनियम हैं, उनमें से बहुत से काफी पुराने हैं तथा अनेक संशोधनों ने इन कानूनों को अस्पष्ट और जटिल बना दिया है। भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों और विनियमों को पुनः लिखने तथा आसान बनाने के लिए एक वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग बनाया है जिससे भारत के तेजी से बढ़ रहे वित्तीय क्षेत्र के साथ तालमेल बनाया जा सके।

## IX. समापनकारी विचार

66. मैंने जोखिम और गवर्नेंस पर अपने यादृच्छिक विचार व्यक्त किए हैं। मैंने संकट के प्रति नियामक अनुक्रिया के बारे में और अंतरराष्ट्रीय तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य दोनों में बासेल III के कार्यान्वयन के मुद्दों के बारे में आपको जानकारी देने की है। जोखिम और गवर्नेंस पर अभी भी अवधारणाएं विकसित हो रही हैं और मुझे विश्वास है कि इस प्रकार की चर्चाएं नीति निर्माण के लिए मूल्यवान सामग्री प्रदान करेंगी। मैं इस प्रकार की शिखर बैठक बुलाने के लिए आईएसबी और डिलॉयट के प्रयासों को बधाई देना चाहता हूँ और कामना करता हूँ कि यह चर्चा सभी प्रकार से सफल हो।

## **संदर्भ:**

1. करुआना जैम (2012) ‘शेयरहोल्डर वैल्यू और स्टेबिलिटी इन बैंकिंग’, इज देयर ए कंफिलक्ट?’
2. डेनियलसन, जॉन, ‘ब्लेम दि मॉडल’, जोर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी 4 (2008)
3. डर्मन, इमैन्युअल (2011), ‘मॉडल्स बिहेविंग बैंडली’फ्री प्रेस
4. डाइबोल्ड, फ्रांसिस एक्स, डोहर्टी, नील ए, हेरिंग, रिचर्ड जे (2010), ‘दि नोन, दि अननोन एंड दि अननोएबल इन फाइनेंशियल रिक्स मैनेजमेंट,’ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस
5. डौड, केविन एंड हुचिसन, मार्टिन ‘‘अलकेमिस्टस ऑफ लास्,’’ टाइम्स ग्रुप बुक्स
6. ग्रुप ऑफ थर्टी, ‘ट्रुवर्ड इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीटयूशन’
7. हल्डने, एंड्रयू जी (2012), ‘टेल्स ऑफ दि अनएक्सपेक्टिड’
8. इंस्टीटयूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनैंस (2009) ‘रिस्क माडल्स एंड स्टैटिस्टिकल मीजर्स ऑफ रिस्क’
9. मोहन राकेश (2007) ‘इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर रिपोर्ट – फॉस्टरिंग ग्रोथ हाइल कंटेनिंग रिस्क’
10. पालसन, हेनरी एम (2010), ‘ऑन दि ब्रिंक’, बिजनेस प्लस, हचेट बुक ग्रुप
11. रिवांन्टो, रिकर्डो (2007) ‘प्लाइट ऑफ दि फारचून टेलर’ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस
12. सीनियर सुपरवाइजर्स ग्रुप (2008), ‘आजर्वेशन्स ऑन रिस्क मैनेजमेंट प्रेक्टिसेज ड्यूरिंग दि रिसेट मार्केट टर्बुलेंस’
13. ... (2009), ‘रिस्क मैनेजमेंट लेसन्स फ्राम दि ग्लोबल बैंकिंग क्राइसेंस ऑफ 2008
14. दि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनैशनल फाइनैंस कार्पोरेशन (2010), ‘बैंक गवर्नेंस लेसंस फ्रॉम दि फाइनेंशियल क्राइसेज’, नोट नवंबर 2013
15. ट्रियाना पेबलो (2009), ‘लेक्चरिंग बर्ड्स ऑन फ्लाइंग’ जॉन विली एंड सन्स आईएनसी।